ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 227-229

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

भारत में कौशल विकास की समस्यायें एवं समाधान

डॉ0 संजय कुमार पाण्डेय
असिस्टेन्ट प्रोफेसर– बी0 एड0 विभाग, श्री म0रा0द0पी0जी0 कालेज, भुड़कुड़ा– गाजीपुर, (उ0प्र0) भारत

Received-20.03.2024, Revised-24.03.2024, Accepted-30.03.2024 E-mail: sanjaysudha15@gmail.Com

सारांशः ***आज के वैश्विकरण के युग में कौशल प्रशिक्षण किसी भी देश के स्वस्थ आर्थिक विकास हेतु बढ़ती कार्यक्षमता एवं उत्पादकता के लिए अनिवार्य घटक है। जबकि भारत में अभी यह प्राथमिक अवस्था में ही है, इस क्षेत्र में विश्व के अन्य देशों से हम काफी पीछे ही चल रहे है, हालांकि विगत कुछ वर्षों में कुशल श्रम शक्ति एवं कौशल विकास की मांग काफी हद तक बढ़ी है। इस खाई को पाटने के लिए ''कौशल परितन्त्र'' की पुर्नरचना की आवश्यकता है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ''स्किल इंडिया'' मिशन प्रोग्राम को गति मिलना प्रारम्भ हुआ। इसमें सभी कौशल विकास गतिविधियों का संचालन करने एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण के संरचना निर्माण और उसके मूल्यांकन के लिए (जिससे देश में कौशल विकास को प्रभावी बनाया जा सके) एक स्वतंत्र कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय बनाया गया है, फिर कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनायी गयी जिसे 15 जुलाई 2015 में लागू किया गया, ताकि कौशल के मानक और स्थिरता के साथ बड़े पैमाने पर लोगों की चुनौतियों का सामना किया जा सकें। कौशल विकास कार्यक्रमों के मध्य अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित किया जा सकें। कौशल विकास वर्तमान समय की मांग है, यह बेरोजगारी दूर करने एवं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक है।***

इसलिए कौशल विकास में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण के प्रकारों की विविधिकरण, गुणवत्ता प्रबन्धन, सार्वजनिक वित्तपोषण एवं संसाधन आदि द्वारा प्रयास किया जा सके। प्रस्तुत अध्ययन में कौशल विकास का महत्व एवं सरकारी प्रयास आदि पर प्रकाश डाला गया है (प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक शोध आकड़ों का प्रयोग किया गया है)।

कुंजीभूत शब्द– कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, कार्यक्षमता, उत्पादकता, अनिवार्य घटक, प्राथमिक अवस्था, विगत, कुशल श्रम।

हमें विकास के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ''कौशल विकास मिशन'' आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भूमिका में आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से शसक्त बना रहा है, इससे हमारे युवाओं का आत्मविश्वास, कौशल, रचनात्मकता एवं बौद्धिक क्षमता के विकास का मार्ग प्रसस्त हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप हम सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है, बच्चों के स्कूली शिक्षा को कौशल विकास के दायरे में लाना ही होगा, ताकि हमारे छात्र में वैश्विक नागरिक बने और भारत एक शसक्त भविष्य की ओर जाय। जैसा कि विदित है कि भविष्य में वे देश ही भविष्य में अपनी वैश्विक पहचान बनाये रखने में समर्थ होंगे जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे इसके लिए कौशल विकास मिशन कारगर हथियार के रूप में काम करेंगी।

वर्तमान में भारत में तकनीकि एवं कौशल ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रयास मिशन के रूप में किये जाने की आवश्यकता है जिससे गरीबी एवं निरक्षता जैसी समस्याओं का निराकरण हो सके। इस दिशा में वैसे अपेक्षित प्रयास किये भी जा रहे है जैसे–सरकार द्वारा सुक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना के लिए अपेक्षित औद्योगिक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में जानकारी देकर युवाओं की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जा रहे है, जिनसे उन्हें स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित करने वाला कौशल उपलब्ध हो सके। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी इसे शिक्षा के हर स्तर पर अनिवार्य/वैकल्पिक रूप सम्मिलित किया है। कौशल विकास वर्तमान सरकार के उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है जिससे की हम अपनी युवा शक्ति का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सके।

शोध पत्र के उद्देश्य– प्रस्तुत शोध अध्ययन को निम्नलिखित शोध बिन्दुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है–

1. कौशल विकास के महत्व को बताते हुए कौशल विकास के प्रति रूझान पैदा करना।
2. भारत में कौशल विकास हेतु आने वाली चुनौतियों से अवगत कराना।
3. कौशल विकास में सरकार की भूमिका का पता लगाना।

शिक्षा एवं कौशल– शैक्षणिक एवं व्यवसायिक शिक्षा के बीच सामंजस्य न होने के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक कौशल के अभाव में शिक्षित युवाओं में कार्यकुशलता एवं बेरोजगारी अधिक है। तकनीकि कौशल के महत्व को समझकर वर्तमान समय में शिक्षा एवं कौशल विकास को नजदीक लाने का प्रयास जारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में इसका पहल किया गया है, परन्तु इसके परिणाम प्रतिक्षित है। शिक्षा प्रकाश की वह ज्योति है, जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा द्वारा कौशल विकास हेतु निम्नलिखित संस्थायें कार्य कर रही है।

शासकीय संस्थान– इसमें आई.टी.आई. कौशल विकास केन्द्र, पालिटेक्नीक, इंजीनियरिंग कालेज, कृषि इंजीनियरिंग कालेज, कृषि विश्व विद्यालय एवं अन्य महाविद्यालय।

अर्ध सरकारी संस्थान– प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाऐं, आई.जे.टी.आर. भारत संचार निगम लिमिटेड आदि।

निजी संस्थान– सेक्टर स्किल काउन्सिल से ऐफलियेटेड निजी प्रशिक्षण प्रदाता संस्थायें एवं इसी तरह की अन्य संस्थान कौशल किसी कार्य को करने की स्थापित विधि है, किसी कार्य को सफलतापूर्वक गुणवत्ता युक्त कार्य करने की क्षमता को ही कौशल

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

कहते है। कौशल व्यक्ति को कार्य कुशल बनाता है अपने गुणों एवं कुशलताओं द्वारा श्रम के द्वारा किये जाने वाले कार्य को ही कौशल विकास कहते हैं, जैसे किसी संस्था के द्वारा कम्प्यूटर कोर्स, ब्यूटी पार्लर कोर्स आदि। वैसे "नो टाईम टू लूज" के अनुसार कौशन तीन प्रकार के होते हैं।

1. संज्ञानात्मक कौशल– इसमें व्यवहारिक ज्ञान एवं समस्या को सुलझाने की योग्यता तथा उच्च संज्ञानात्मक कौशल जैसे प्रयोग एवं रचनात्मकता शामिल होते है।

2. तकनीकि एवं व्यावसायिक कौशल– यह किसी भी व्यवसाय में उपकरणों एवं विधियों का उपयोग कर विशिष्ट कार्य करने की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को दिखाता है।

3. सामाजिक एवं व्यवहारिक कौशल– इसमें व्यक्ति समाज में कैसे व्यवहारिक समायोजन करता है इसका ज्ञान दर्शाता है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि शिक्षा का मूल लक्ष्य केवल रोजगार प्राप्त करना ही न हो कर बल्कि इसका व्यापक स्वरूप है। सामान्य शैक्षणिक प्रणाली में उपरोक्त कौशलों का समावेश अधिक बेहतर ढंग से हो पाता है, इसके अतिरिक्त कौशल विकास व्यवसायिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पेशेवर जीवन में प्रवेश का रास्ता आसान करता है।

कौशल विकास की प्रासंगिकता– कौशल विकास की प्रासंगिकता भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता एवं रोजगार तक व्यक्ति के पहुँच की कुँजी है। वर्तमान समय में अधिकांश व्यक्तियों में बेरोजगारी को देखते हुए कौशल का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम अपनी प्रतिभा को प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा आगे लाकर रोजगार प्राप्त करते हैं, जैसे कौशल विकास के प्रासंगिकता को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

- छात्रों में व्यवहारिक एवं क्रियाशील कौशल का विकास करना जो उन्हें रोजगार प्रदान कर सके। जो वर्तमान समय की मांग है।
- रोजगार आधारित कौशल व्यापक विशेषताओं की ओर ले जाता है जिससे छात्र की प्रभावकारिता बढ़ती है।
- कौशल विकास के द्वारा व्यक्ति की उत्पादन क्षमता का विकास होता है जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है।
- कौशल विकास के द्वारा जीवन स्तर में सुधार होता है जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव होता है।
- कौशल विकास हमें स्वयं कुशल बनाकर स्वरोजगार की ओर प्रेरित करता है।
- कौशल विकास व्यक्तिगत आय के साथ–साथ देश की अर्थ व्यवस्था भी सुदृढ़ होती है।
- कौशल विकास के द्वारा नवयुवकों, महिलाओं एवं वंचित समुह के लिए रोजगार के अवसर का सृजन होता है।

कौशल विकास की समस्यायें– कौशल विकास की प्रोत्साहन देना समय की मांग है परन्तु इसके विकास के मार्ग में अनेक समस्यायें है जिससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे है–

1. ग्रामीण एवं शहरी विभाजन– भारत में इन दोनों ही क्षेत्रों में आबादी का प्रवास है परन्तु इन क्षेत्रों में अवसर की उपलब्धता एवं संसाधनों की उपलब्धता में पर्याप्त अन्तर होने के कारण परिणाम में विभिन्नता देखने को मिलती है।

2. उद्यमिता कौशल की कमी– प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में यह अपेक्षा की गयी थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद लोग स्वरोजगार की ओर मुड़ेगे परन्तु आकड़ों से पता चलता है कि केवल 24 प्रतिशत लोग ही स्वरोजगार की ओर मुड़े।

3. उद्योगों की सीमित भूमिका– अधिकांश प्रशिक्षण संस्थाओं में उद्योग क्षेत्र की भूमिका सीमित होने के कारण प्रशिक्षण की गुणवत्ता संदग्धि बनी रहती है जिससे रोजगार एवं वेतन का स्तर निम्न बना रहा है।

4. अपर्याप्त प्रशिक्षण क्षमता– भारत में गुणवत्तापरक प्रशिक्षण न प्राप्त होने के कारण ढंग का रोजगार का अवसर नहीं मिल पाता है इसके अलावा प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं में भी कुशल प्रशिक्षकों का अभाव देखा जाता है।

5. विद्यार्थियों का कम आकर्षण– प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों में जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं पालीटेक्नीक संस्थानों में कम नामांकन हो रहा है, क्योंकि इन संस्थाओं में गुणवत्ता का अभाव होने के कारण उन्हें रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

6. अनुपयुक्त कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम– वर्तमान में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम वर्तमान की आवश्यकता के अनुरूप न होने के कारण इनके प्रशिक्षणार्थियों की उद्योगों में कम मांग होती है।

7. बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई– रोजगार या व्यवसाय हेतु बैंकों से आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है जिसके लिए उन्हें बैंकों से कौशल ऋण योजना या बैंकों से ऋण प्राप्त करने में अनेक बाधायें प्राप्त होती है। जिसके वजह से रोजगार प्राप्त करने में पीछे रह जाते है।

8. सामाजिक समस्यायें– भारत जैसे देश में जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते है ऊँच–नीच, अमीरी–गरीबी जैसी समस्यायें भी कौशल विकास के मार्ग में बाधक के रूप में कार्य करती है।

कौशल विकास के लिए राजकीय पहल– कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा की गयी पहल निम्नलिखित है–

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग– सन् 2010 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विभाग का गठन किया गया था। जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को तकनीकि एवं रोजगार आधारित शिक्षा देना था।

कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय– सन् 2014 में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया गया जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण प्रक्रिया में बेहतर तालमेल स्थापित करना एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण एवं विकास करना था।

स्किल इंडिया कार्यक्रम– प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 को स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत की थी। इस योजना से ऐसे लोगों को सक्षम बनाना था, जो वास्तव में कुछ करके स्वयं के जीवन में परिवर्तन चाहते है लेकिन उनके पास जरिये का अभाव है, इस

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-17, No.- I, Issues-31, YEAR- Jan.-March-2024

मुहिम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना जहा पर निःशुल्क या अत्यन्त कम शुल्क पर कौशल को विकसित किया जा सके।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKY)– इस योजना के तहत युवाओं को कम अवधि का (150–300 घंटे) कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। इससे प्राप्त प्रशिक्षुओं को सरकारी योजना में जैसे–मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते है। इसमें उन्हें प्रशिक्षण के उपरान्त एक प्रमाण–पत्र भी दिया जाता है जो सभी जगह मान्य है।

प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र– इसकी परिकल्पना अत्याधुनिक माडल प्रशिक्षण केन्द्र के संस्थान के रूप में की गयी है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम– इसकी स्थापना एक राष्ट्रीय कौशल मिशन के अन्तर्गत भारत के सभी क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति की बढ़ती आवश्यकता को पूर्ण करने तथा कौशल की मांग एवं आपूर्ति के बीच मौजूदा अन्तराल कम करने के लिए की गयी है।

निष्कर्ष– अन्त में यह कहा जा सकता है कि भारत में कौशल विकास एवं बेरोजगारी की समस्या के मूल में माध्यमिक स्तर (स्कूल स्तर) पर व्यवसायिक शिक्षा को पूर्ण स्थान न मिल पाना तथा विभिन्न कौशल विकास योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वन है। स्किल इंडिया जैसे– कार्यक्रमों ने अपेक्षित परिणाम नहीं प्रदान किया है जिससे कि बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान हो सके। भारत को विकसित देशों एवं पूर्वी एशिया के देशों से प्रेरणा लेकर अपनी स्थानीय समस्याओं के अनुसार इन कौशल विकास योजनाओं को सशक्त बनाकर क्रियान्वयन कर सकता है। विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का वाक्यांश ''लर्निंग शुड नॉट स्टॉप फ्राम अर्निंग''। उनकी यह युक्ति व्यक्ति और राष्ट्र कौशल विकास में सहायक होगी। इस प्रकार हम कह सकते है कि कौशल विकास के लिए सरकार, उद्योग एवं शिक्षण संस्थाओं को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हम देश को शक्तिशाली एवं समृद्ध बना सके।

सुझाव– भारत में कौशल विकास की समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं।

1. शिक्षा प्रणाली में सुधार– शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार को गुणवक्ताहीन शिक्षा को दूर करने बुनियादी ढ़ाचे में सुधार करने और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

2. कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार– इसके विस्तार के दृष्टी से सरकार को उद्योगों से मिलकर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने एवं उन्हें युवाओं तक पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए।

3. रोजगार के अवसरों का सृजन– इसके लिए सरकार को उद्योगों को प्रोत्साहित करने और उन्हें समर्थन देने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि वे अधिक रोजगार के अवसर प्रदान कर सके।

4. सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को दूर करना– इसके लिए सरकार को सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रमों को विकसित करने और उन्हें सामर्थवान बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

5. प्रशिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन– समय–समय पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को इन संस्थाओं का मूल्यांकन एवं इनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए।

6. कौशल का विकेन्द्रीकरण– स्थानीय संसाधनों के उपयोग से स्थानीय विकास के लिए स्थानीय लोगों को ही अवसर प्रदान करते रहना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. https//www.dhyeyaias.in/
2. https//www.drishiias.com/
3. https//itpd.ncevt.gov.in/
4. https/www.mpskills.gov.in/
5. https/www.oppertunitvindia/
6. pardhan mantri kaushal vikash yojna.mpkvyofficial.org
7. https/www.researchgate.net/
8. https/www.snaskritia.com
9. कुमार आलोक, (मार्च–2017) योजना।

*****